



"युद्ध अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेदले फिलिप

# दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 10 जुलाई 2026 शुक्रवार

## सम्पादकीय

### जनगणना में जाति की गिनती

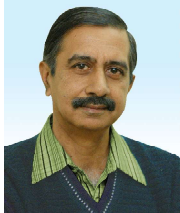
जनगणना 2027 के दूसरे चरण का रिहसल 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 6 जुलाई से चल रहा है, जिसमें मुख्य खासियत है एक 'खुला कॉलम' जिसमें लोग अपनी जाति बता सकते हैं जिसे गणनाकर्ता दर्ज करेंगे। साल 2011 की 'सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी)' में भी यह खासियत थी, लेकिन उसके उलट सीधे जनगणना में जाति की इस गिनती को बेवैधानिक सम्पन्न प्रांत हैं। पूर्व-परीक्षण 20 जुलाई को खत्म हो रहा है और सरकार का कहना है कि इसके बाद वह जाति गिनती के तरीके को अनिश्चित रूप देगी। उन्मीद है कि पूर्व-परीक्षण के निष्कर्ष पहले से ज्ञात बावत की पुष्टि करेंगे जो जाति के बारे में अस्पष्ट (ओपन-एंडेड) जवाब से केवल ऐसा डेटा मिलता है जिसे सामंजस्य पाना मुश्किल होता है, जैसा कि साल 2011 में एसईसीसी में देखा गया था, जो आधिकारिक किसी काम का नहीं साबित हुआ। यह समझना कठिन नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। इस तरीके की वजह से एसईसीसी 2011 में 46 लाख से अधिक 'जाति नाम' सामने आए थे, जबकि साल 1931 की जनगणना में वह आठवीं जनगणना जिसमें जाति की गिनती की गयी थी, यह संख्या 4,147 थी। उत्तरदाताओं ने उपनामों, उप-जातियों और कुल नामों, जिनका इस्तेमाल शायद एक-दूसरे की जगह हो सकता था, को दर्ज किया, जिससे यह गिनती बढ़कर बेमतलब बन गयी। केंद्र सरकार ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एसईसीसी के आंकड़ों में इतनी त्रुटियां हैं कि आरक्षण के लिए उन पर मरौसा नहीं किया जा सकता। बजाय इसके, पूर्व-परीक्षण को एक बेहतर तरीका पेश करना चाहिए जो डिजिटल जनगणना के हैंड-हेल्ड डिवाइसों का इस्तेमाल करना, जिनमें जातियों और उप-जातियों की एक संवारी हुई सूची पहले से लोड हो, ताकि गणनाकर्ता उत्तरदाता से पुश्तकर 'सही' प्रतिक्रिया चुने। गलतियां और बेमेलन होंगे, लेकिन जैसा कि साल 2022-23 के बिहार जाति सर्वेक्षण से जाहिर हुआ, यह तरीका ज्यादा काम का डेटा दे सकता है।

जनगणना में नोट की जाने वाली दूसरी पहचानों कृ पात्रा, धर्म और लिंग क के उलट जाति एक अमूर्त और आतंकिक पहचान है जो लोगों की शिनाखत उनकी जैविक, शारीरिक या धोषित विशेषताओं से नहीं, बल्कि उस मानी हुई, आदिमयुगिनी पहचान से करती है जो जन्म-प्रदत्त और ऊंच-नीच की व्यवस्था में बली होती है। यह ऊंच-नीच भी सुस्पष्ट नहीं है, क्योंकि अलग-अलग जातियों के सामाजिक दर्ज को लेकर लोगों की धारणाएं अक्सर एक-दूसरे के विपरीत होती हैं। सामाजिक न्याय के लिए प्रतिक्रिया भारत के संविधान ने छुआछूत खत्म करके, जाति-आधारित भेदभाव पर रोक लगाकर और एक ऐसे गणतंत्र का वादा करके जहां किसी नागरिक की हैसियत जन्म से तय नहीं होगी, खुद को जाति के विरोध में खड़ा किया। तो फिर जाति की गिनती क्यों की जाए, जब खुद गिनती करने की प्रक्रिया इस अमूर्त पहचान को कठोर या मूर्त बना सकती है? एकमात्र औचित्य यह है कि खुद से मानी हुई या थोपी हुई जातिगत पहचान सामाजिक असमानताएं पैदा करती है, और जाति-आधारित संस्थाओं को दूर करने वाले कल्याणकारी व सामाजिक न्याय के उपायों से अन्वय के साथ यह उलटकर बनाता है कि वे जातिवादी को मजबूत करने के बजाय उसकी बेवैता नष्ट करेंगे। कल्याणकारी योजनाओं और सकारात्मक कार्रवाइ को ज्यादा सटीक ढंग से लक्षित करने के क्रम में, वास्तविक जातिगत आंकड़े आरक्षण से पहले से लगायित हो रही जातियों व वर्गों के उप-वर्गीकरण और क्रीमीलाइजेशन से जुड़े सवालों पर भी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। इन मामलों में बेहतर अंकों बहुत जरूरी हैं। अगर जाति गिनी जानी है, तो फिर ठीक से गिनी जानी चाहिए। इसे दर्ज करने का अस्पष्ट (ओपन-एंडेड) तरीका गंभीर त्रुटि भरसक को पूरा नहीं करेगा।

### बद्रीनाथ धाम में दान प्रबंधन पर सवाल

जान मन्मथि त्रिभुवन्ध्र न्यास में गदान का मामला अभी शक भी नहीं हुआ था कि बद्रीनाथ धाम में बैसरी ही अनियमितता का प्रकरण सामने आने से मंदिरों में सन्सृष्टी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। चढ़ावे की राशि में वित्तीय हंगामेरी का जो स्वरूप पिछले त्रिनि सामने आया है, उससे करोड़ों लोगों की आस्था को ट्रेस पहुंची है। अब बद्रीनाथ धाम में दान राशि के प्रबंधन में गडबडीयों के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। साथ ही मंदिर समिति के अध्यक्ष कार्यालय में तैनात जाति सहायक को निलंबित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सवाल है कि जिन कर्मचारियों पर दान राशि को गिने और जमा करने की जिम्मेदारी है, उन पर निगरानी का सुव्यवस्था तंत्र अब तक क्यों नहीं बनाया गया। अगर श्रद्धालुओं के पैसे को ताक पर रखकर पैसे का बेरोक-टोक गणन हो रहा है, तो इसके लिए मंदिर के पूरे प्रशासनिक अमले को जवाबदेह होना चाहिए। इसमें दोषयन नहीं कि जिन राशि के प्रबंधन में पारदर्शिता के लिए व्यापक निगरानी तंत्र न होने की वजह से ही अथोव्या के लिए मंदिर के प्रबंधन व्यवस्था उभार तक वित्तीय अनियमितता के मामले सामने आ रहे हैं। गडबडीयां समाप्त होने के बाद सरकार की जांच से जांच को लेकर जो गंभीरता दिखाने का प्रयास किया जाता है, अगर वह सतीकर्तता और कड़ाई पहले दिखाई जाए, तो क्या कोई लोगों की आस्था के साथ इस तरह खिलवाव करने की हिमत कर पाएगा? इन मामलों से जो जाति और वर्गों की उपरकर सामने आए हैं, वह मंदिरों की प्रबंधन व्यवस्था पर चुनौती के दिशारास को बनाए रखने की है। दोनों ही जगह कर्मचारियों की नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं बरतने पर भी सवाल उठ रहे हैं। बद्रीनाथ जाति रास से लेकर उसकी गिनती वाले धोयन तक अगर सीधीसीटी से कड़ी नजर रखी जाए, तो निश्चित रूप से गडबडीयां समथ रहने पडक में आ सकती थी। आज सरकार की जांच से जवाबदेही तय करने और पारदर्शिता की जो बातें कही जा रही हैं, अगर इसका पहले से अनुपालन किया गया होता, तो जाहिर है कि हेराफेरी की कोई गुंजाइश नहीं रहती।

# ठंडे पानी से मौनसून में बदलाव और किसान



—मुकुल व्यास—

एक नई रिसर्च से पता चलता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पानी के एक ठंडे हिस्से ने जेट स्ट्रीम हवाओं के जरिए भारतीय गर्मियों के मौनसून में बदलाव शुरू कर दिए हैं। इससे करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी को खतरा पैदा हो गया है। मौनसून हमारी जीवन रेखा है। भारत और दक्षिण एशिया के दूसरे हिस्सों में। अगर ये अधिक लोग खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए मौनसून पर निर्भर हैं। हर साल हम एक अच्छे मौनसून की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने पया है कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय मौनसून के पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है। वैज्ञानिक इस बदलाव के कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक नई रिसर्च से पता चलता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पानी के एक ठंडे हिस्से ने जेट स्ट्रीम हवाओं के जरिए भारतीय गर्मियों के मौनसून में बदलाव शुरू कर दिए हैं। इससे करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी को खतरा पैदा हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दोनों प्रणालियों के बीच का संबंध एक ऐसे पहले से अज्ञात संबंध को



दिखाता है जो दक्षिण एशिया में मौसम के अनुमानों को जानकारों के लिए एक ठंडे हिस्से ने जेट स्ट्रीम हवाओं के जरिए भारतीय गर्मियों के मौनसून में बदलाव शुरू कर दिए हैं। इससे करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी को खतरा पैदा हो गया है। मौनसून हमारी जीवन रेखा है। भारत और दक्षिण एशिया के दूसरे हिस्सों में। अगर ये अधिक लोग खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए मौनसून पर निर्भर हैं। हर साल हम एक अच्छे मौनसून की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने पया है कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय मौनसून के पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है। वैज्ञानिक इस बदलाव के कारणों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक नई रिसर्च से पता चलता है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पानी के एक ठंडे हिस्से ने जेट स्ट्रीम हवाओं के जरिए भारतीय गर्मियों के मौनसून में बदलाव शुरू कर दिए हैं। इससे करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी को खतरा पैदा हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दोनों प्रणालियों के बीच का संबंध एक ऐसे पहले से अज्ञात संबंध को

की थी। लेकिन 1999 से यह पैटर्न बहुत बदल गया है। शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन में पाया कि उत्तर-पश्चिम भारत में बहने वाले मौनसून सौजन में 1999 से पहले के मुकाबले लगभग 25 प्रतिशत ज्यादा बारिश होती है जबकि गंगा के मैदानी इलाकों में लगभग 4 प्रतिशत कम बारिश होती है। इस अध्ययन के पहले लेखक और भारतीय विज्ञान संस्थान के जलवायु वैज्ञानिक महेंद्र निम्माकानि ने कहा कि यह परिवर्तन किसानों के लिए खास तौर पर बहुत बुरा है, क्योंकि उनके खेतों की मिट्टी और फसलें बारिश के पुराने पैटर्न के हिसाब से ढल गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत काकरी हद तक खेती पर निर्भर है। उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक बारिश होकर पर अनाजक बढ आ जाती है और फसलों का नुकसान होता है, क्योंकि इस इलाके की खेती सूखे हालात के हिसाब से ढल गई है। इस बीच,

गंगा के मैदानी इलाकों में सूखे के दौर भी आए हैं, जिससे फसलों में भी कमी आई है और किसानों की रोजी-रोटी पर असर पडा है। पिछले अध्ययनों में भारतीय मौनसून में परिवर्तन को अटलांटिक मेरिडियनल ओवरड्रिफ्ट सर्कुलेशन (एएमओसी) में बदलाव से जोडा था। एएमओसी अटलांटिक में समुद्री धाराओं का एक बडा जाल है जो वैश्विक जलवायु को नियमित करता है और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पहुंचाता है। आंकड़े बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से एएमओसी भी ठंडा है और उत्तरी अटलांटिक महासागर में पहले के मुकाबले कम गर्मी छोड रहा है। निम्माकानि ने कहा कि इन अध्ययनों में यह नहीं बताया गया कि भारतीय मौनसून कैसे बदल सकता है। इसके पीछे के तंत्र को भी विस्तार से नहीं समझाया गया। उन्होंने कहा, ये अध्ययन आम तौर पर यह समझाते हैं कि अगर एएमओसी कमजोर होता

है, तो यह भारतीय मौनसून को भी कमजोर करता है। एक बडी समस्या यह है कि मौजूदा जलवायु मॉडल भारतीय मौनसून में ह्रुप बदलावों को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वे उत्तरी अटलांटिक महासागर की सतह के तापमान में बदलाव को भी पूरी तरह से गृहण नहीं करते हैं। इन मॉडलों ने ग्रीनलैंड के दक्षिण-पूर्व में एक अत्यंत ठंडे क्षेत्र पर गौर नहीं किया जिसे 'कोल्ड ब्लॉक' के नाम से जाना जाता है, जहां 1901 और 2021 के बीच पानी 1800 के दशक के आखिर की तुलना में ज्यादा ठंडा था। कोल्ड ब्लॉक बताया है कि एएमओसी कमजोर हो रहा है क्योंकि यह उत्तरी अटलांटिक तक पहुंचने वाली गर्मी की मात्रा में कमी की और इशारा करता है।

यह पता लगाने के लिए कि भारतीय मानसून कैसे और क्यों बदल रहा है, शोधकर्ताओं ने दर्जनों जलवायु मॉडलों में बारिश का डेटा, समुद्र की सतह के तापमान के रिकॉर्ड और असल जिनदी के दूसरे अवलोकन डाले। इसने पिछले 27 सालों में देखे गए बदलावों को फिर से दिखाया। इन नतीजों से उत्तरी अटलांटिक में ह्रुप बदलावों और मौनसून में बदलावों के बीच संबंध का पता चला। यह जानने के लिए क्या उत्तरी अटलांटिक समुद्र की सतह के तापमान की वजह से भारतीय मानसून अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है, टीम ने एक सिमुलेशन (कंप्यूटर पर परिस्थितियों की नकल) में कोल्ड ब्लॉक को जोडा और हटाया। नतीजों से पता चला कि ठंडे ब्लॉक ने उत्तरी अटलांटिक के एक मजबूत टैम्परेचर ग्राडिएंट (तापमान

में परिवर्तन) की दर और दिशा को शिफ्ट कर दिया है, जो बदले में यूरेशिया के ऊपर वायुमंडल में जेट स्ट्रीम हवाओं और प्रेशर सिस्टम पर असर डालता है। खासकर, उत्तरी अटलांटिक के ऊपर जेट स्ट्रीम तेज हो गई है, और पश्चिमी रूस में यूराल पहाड़ों के ऊपर एक 'ब्लॉकिंग' सिस्टम मजबूत हो गया है। इसके परिणामस्वरूप भारत में मौसम सिस्टम बदल गए हैं, जो नयी वाली हवा को देश के उत्तर-पश्चिम की ओर ले जा रहे हैं और उसे दूसरे इलाकों से दूर खींच रहे हैं। एजीयू एडवांसेज जर्नल में छपे नए नतीजों से मौसम का अनुमान लगाने वालों को भारत और पड़ोसी देशों में मौनसून के दौरान बहुत ज्यादा बारिश और सूखे जैसी घटनाओं का अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि भारतीय मौनसून वैश्विक जलवायु में एक निर्णायक बिंदु (टिपिंग प्वाइंट) है, और इन निष्कर्षों से पता चलता है कि यह सिस्टम 1999 में एक अहन सीमा पार कर गया था। जब से कोल्ड ब्लॉक की वजह से जेट स्ट्रीम ने लगातार बर्ताव हुआ है, जिससे मौनसून में अनाजक बदलाव आए हैं। अभी यह साफ नहीं है कि जेती से बदरती जलवायु भारतीय मौनसून कैसे बदलेगा, क्योंकि जलवायु मॉडल उत्तर अटलांटिक के बारे में अलग-अलग अनुमान लगाते हैं, और दुनिया के बदलने के साथ-साथ दूसरे कारण भी असर डाल सकते हैं।

लेखक विज्ञान मामलों के जानकार हैं।

## चढ़ावा चोरी: संघ साधना पर वज्राघात

### —डॉ० मत्स्येन्द्र प्रमाकर—

अथोव्या स्थित राम मन्दिर न केवल ऐतिहासिक बल्कि भारत की सनातन परम्परा एवं संस्कृति का अद्वितीय प्रतीक है। लगभग पाँच शताब्दी के उपरांत पुनर्निर्माण से इसकी महत्ता और बढ़ी है। इस मन्दिर में होने वाले चढ़ावे में चोरी की घटना जैसे, और जिस भी परिस्थिति में हुई वह अत्यन्त चिन्तनीय, दुःखद, निन्दनीय तथा शर्मनाक भी है। मन्दिर का प्रबन्धन देश की सरकार के द्वारा गठित और समर्पित ट्रस्ट देखाता है। इसमें उन लोगों का बर्बर है जो उस संगठन से सम्बन्ध है जो देश का सबसे पुराना ही, नही, दुनिया का विशाल संगठन है। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम से एक शताब्दी से कार्यरत और ख्यात है। ऐसी दशा में चोरी की घटना संघ की साधना के साथ केन्द्र सरकार की प्रसिद्धि पर भी आधारित है। चढ़ावा चोरी के मामले में संघ के सरकारीवादी दस्तावेज होसबोले की घटना के प्रकाश में आने के २५वें दिन 4 जुलाई को आगे बढाने में इसकी गम्भीरता को और विकलाल कर दिया है। यह निश्चित ही एक बेहद नया-तुला और संसुलित बयान है किन्तु इससे अधिक कुछ कहा भी क्या जा सकता है।



कारिक बयान, एफआईआर, जिन तारीखों की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और आन्तरिकब्यवहारी ऑडिट रिपोर्ट, निरैसक के अनुदान प्रमातिर करना विधानिक शिथिलसमीक्षा और सामाजिक की व्यवस्थाओं से लिए शाहिकारक होगा। दुर्भाग्य से यह बहदावत में हो रहा है। उचित लेख का तात्पर्य यह रहे आरोपों की निष्पक्ष, भ्रंशिक तथा सम्पन्नबद्ध जांच आवश्यक है, और उसी के आधार पर संस्थागत व व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित होनी चाहिए।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दशकों में अपनी एक विशिष्ट सांजनिनिक छवि बडी हेतु संगठित अनुशासन, सेवाभाव और नैतिक चरित्र पर जोर। यही छवि संघ के सम्बन्धों और उससे जुड़े संगठनों के लिए उम्मीदों का मानपट्टण भी बनती है। जब संघ, समर्पित व्यक्ति या संस्था राम मन्दिर जैसी परियोजनाओं के सञ्चालन में अनुसूच्य होते हैं, तब उनसे बडे प्रमुखता और नैतिकता की अपेक्षा तन्त्र: जुड जाती है। यह प्रबन्धन स्तर पर लेखा-जातिया, सुरक्षा और पारदर्शिता की कमियां दिखाई देती तो यह केवल व्यक्तिगत निन्दनिक ही रासनाप्रतिष्ठा का भी प्रभाव डालेगा। इसलिए संघ का स्वाभाविक दायित्व बनता है कि वह जाँच और सुधार की प्रक्रिया में सक्रिय, पारदर्शी और जवाबदेह भूमिका निभाये, बजाय केवल प्रतिष्ठाकर्म के।

जोडियम बढाती है। तीसरा, मानव संसाधन नैतिककरण बैकयाउआर, के, नियमित रेटोरान और प्रशिक्षण का अभाव केंद्रीकृत पहुँच के संगठन देता है। चौथा, राजनीतिक-संस्थागत निकटताकृत प्रबन्धन और केन्द्र के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहते हैं तो जांच और जवाबदेही पर दबाव बन सकता है जिससे सतत पारदर्शिता बाधित हो सकती है।

## तेजी से अराजकता की ओर बढ़ रहा देश

### —गंगत राम पासला—

देश तेजी से अराजकता की ओर बढ़ रहा है। अराजकता, जिन किसी एक के सरकारों के अविश्वसनीयक प्रदर्शन से उभरे लोगों के स्वरूपसूक्त गुरसे में से पैदा होती है। परंतु लुटेरी श्लाक जमात और इनके मोहरें बने प्रतिक्रियावादी तंत्र भी इसे अक्सर हवा देते हैं। सांप्रदायिक नफरत, कट्टरवाद, अविश्वास और हिंसा का जिस किस्म का तांडव आग नाया जा रहा है, वह आजादी प्राप्ति के बाद पहला कभी नहीं देखा गया। 1975 में, तो की कांसेरी सरकार ने सतत पर कब्जा बनाए रखने की एकाधिकारवादी इच्छा के तहत देशराज्यीय पर आंतरिक आपातकाल घोषा दिया था। लेकिन विभिन्न कभी राष्ट्रीयताओं और जातियों से संबधित अलग-अलग प्रांतों में रहने वाले देशराज्यी आपातकाल घोषित होने के कुछ समय बाद इस स्वयंभू विरोधी कृत्य के खिलाफ एकजुट होने शुरू हो गए थे। 1977 में ह्रुप लोकसभा चुनावों के दौरान भारतीय आमम की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता के कारण कांग्रेस पार्टी को ताराशी हार का मूढ देहना पडा था। करारी शक्ति का अंत हो गया था और संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक मूल्य फिर से बहाल हो गए थे।

परंतु साल 2014 में बाव से लगातार चली आ रही भाजपा ने नेटेल वाली केंद्र की मोदी सरकार ने देश के संविधान की मूल प्रस्तावनाओं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की धोयनबाद धमियां उडाई हैं। ए.एस.एस.ए. से दिशा-निर्देशों के तहत राज-काज चला रही मोदी सरकार का यह कारनामा, मूल रूप में 1975 में घोषित आपातकाल से ही ज्यादा खतरनाक है। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, ई.टी.सी.डी.आई. आदि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थान संविधान-कानून मार्गदर्शन में अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। बल्कि मोदी की सरकार के संक्षय में आर.एस.ए. की विचारधारा के अनुसार कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उस पर सितम यह कि प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रहेगी।

अथोव्या का राम मन्दिर आज केवल धार्मिक संस्थाक नहीं रहया वह राष्ट्रीय सम्मान, सांस्कृतिक प्रतीक और राजनीतिक उपलब्धि का समर्पित प्रतीक बन चुका है। ऐसे संवेदनशील स्थल पर परिस्तर से चढ़ावा साधना की चोरी जैसी घटना न सिर्फ अपराध की श्रेणी में आती है बल्कि सार्वजनिक विश्वास, संगमगात जवाबदेही और उन संस्थाओं की नैतिक साख पर भी प्रश्न उठती है। निम्नके नाम और प्रतीकमूय से यह परिचोयना जुडी है। जब प्रबन्धन, ढाँचे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) से जुड़े व्यक्तियों और केन्द्र के निकट सहयोगी का सम्बन्ध हो, तब यह मामला आजादी के मन में 'साधना' और 'प्रबन्धन' के बीच खिचाव की बहस भी खडी कर देता है।

मौडिया कवरेज और आर्थिक सुरक्षाओं के अनुसार मन्दिर परिसर में रखे कुछ चढ़ावे गाइड वही संचालन आयी। सार्वजनिक बस में चम्पय राय बंसल व अनिल मिश्र जैसे नाम बार.बार आये हेंद ये नाम उस संघचना से जुड़े रहे हैं जो मन्दिर के प्रशासन और सम्बन्ध में भूमिका निभाती हैं। तथ्यों की सटीक पुष्टि के लिए मीडिया कवरेज में राम मन्दिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आदि

जोडियम बढाती है। तीसरा, मानव संसाधन नैतिककरण बैकयाउआर, के, नियमित रेटोरान और प्रशिक्षण का अभाव केंद्रीकृत पहुँच के संगठन देता है। चौथा, राजनीतिक-संस्थागत निकटताकृत प्रबन्धन और केन्द्र के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहते हैं तो जांच और जवाबदेही पर दबाव बन सकता है जिससे सतत पारदर्शिता बाधित हो सकती है।

परंतु साल 2014 में बाव से लगातार चली आ रही भाजपा ने नेटेल वाली केंद्र की मोदी सरकार ने देश के संविधान की मूल प्रस्तावनाओं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की धोयनबाद धमियां उडाई हैं। ए.एस.एस.ए. से दिशा-निर्देशों के तहत राज-काज चला रही मोदी सरकार का यह कारनामा, मूल रूप में 1975 में घोषित आपातकाल से ही ज्यादा खतरनाक है। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, ई.टी.सी.डी.आई. आदि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थान संविधान-कानून मार्गदर्शन में अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। बल्कि मोदी की सरकार के संक्षय में आर.एस.ए. की विचारधारा के अनुसार कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उस पर सितम यह कि प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रहेगी।

जोडियम बढाती है। तीसरा, मानव संसाधन नैतिककरण बैकयाउआर, के, नियमित रेटोरान और प्रशिक्षण का अभाव केंद्रीकृत पहुँच के संगठन देता है। चौथा, राजनीतिक-संस्थागत निकटताकृत प्रबन्धन और केन्द्र के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहते हैं तो जांच और जवाबदेही पर दबाव बन सकता है जिससे सतत पारदर्शिता बाधित हो सकती है।

परंतु साल 2014 में बाव से लगातार चली आ रही भाजपा ने नेटेल वाली केंद्र की मोदी सरकार ने देश के संविधान की मूल प्रस्तावनाओं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की धोयनबाद धमियां उडाई हैं। ए.एस.एस.ए. से दिशा-निर्देशों के तहत राज-काज चला रही मोदी सरकार का यह कारनामा, मूल रूप में 1975 में घोषित आपातकाल से ही ज्यादा खतरनाक है। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, ई.टी.सी.डी.आई. आदि संवैधानिक और स्वायत्त संस्थान संविधान-कानून मार्गदर्शन में अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। बल्कि मोदी की सरकार के संक्षय में आर.एस.ए. की विचारधारा के अनुसार कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। उस पर सितम यह कि प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रहेगी।

मौडिया कवरेज और आर्थिक सुरक्षाओं के अनुसार मन्दिर परिसर में रखे कुछ चढ़ावे गाइड वही संचालन आयी। सार्वजनिक बस में चम्पय राय बंसल व अनिल मिश्र जैसे नाम बार.बार आये हेंद ये नाम उस संघचना से जुड़े रहे हैं जो मन्दिर के प्रशासन और सम्बन्ध में भूमिका निभाती हैं। तथ्यों की सटीक पुष्टि के लिए मीडिया कवरेज में राम मन्दिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आदि

जोडियम बढाती है। तीसरा, मानव संसाधन नैतिककरण बैकयाउआर, के, नियमित रेटोरान और प्रशिक्षण का अभाव केंद्रीकृत पहुँच के संगठन देता है। चौथा, राजनीतिक-संस्थागत निकटताकृत प्रबन्धन और केन्द्र के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहते हैं तो जांच और जवाबदेही पर दबाव बन सकता है जिससे सतत पारदर्शिता बाधित हो सकती है।

जोडियम बढाती है। तीसरा, मानव संसाधन नैतिककरण बैकयाउआर, के, नियमित रेटोरान और प्रशिक्षण का अभाव केंद्रीकृत पहुँच के संगठन देता है। चौथा, राजनीतिक-संस्थागत निकटताकृत प्रबन्धन और केन्द्र के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहते हैं तो जांच और जवाबदेही पर दबाव बन सकता है जिससे सतत पारदर्शिता बाधित हो सकती है।

जोडियम बढाती है। तीसरा, मानव संसाधन नैतिककरण बैकयाउआर, के, नियमित रेटोरान और प्रशिक्षण का अभाव केंद्रीकृत पहुँच के संगठन देता है। चौथा, राजनीतिक-संस्थागत निकटताकृत प्रबन्धन और केन्द्र के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहते हैं तो जांच और जवाबदेही पर दबाव बन सकता है जिससे सतत पारदर्शिता बाधित हो सकती है।

जोडियम बढाती है। तीसरा, मानव संसाधन नैतिककरण बैकयाउआर, के, नियमित रेटोरान और प्रशिक्षण का अभाव केंद्रीकृत पहुँच के संगठन देता है। चौथा, राजनीतिक-संस्थागत निकटताकृत प्रबन्धन और केन्द्र के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहते हैं तो जांच और जवाबदेही पर दबाव बन सकता है जिससे सतत पारदर्शिता बाधित हो सकती है।

जोडियम बढाती है। तीसरा, मानव संसाधन नैतिककरण बैकयाउआर, के, नियमित रेटोरान और प्रशिक्षण का अभाव केंद्रीकृत पहुँच के संगठन देता है। चौथा, राजनीतिक-संस्थागत निकटताकृत प्रबन्धन और केन्द्र के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहते हैं तो जांच और जवाबदेही पर दबाव बन सकता है जिससे सतत पारदर्शिता बाधित हो सकती है।



